(IJRSSH) 2013, Vol. No. 3, Issue No. II, Apr-Jun ISSN: 2249-4642

JANATA GOVERNMENT AND BACKWARD CLASS PARTICIPATION IN UTTAR PRADESH

Chandrabhan Yadav

Research Scholar, Department of History

Jamia Millia Islamia, New Delhi

उत्तर प्रदेश में जनता सरकार और पिछड़ा वर्ग की भागीदारी

चन्द्रभान यादव (शोध छात्र)
इतिहास विभाग
जामिया मिल्लिया इस्लामिया
नई दिल्ली

IJRSSH

स्वतंत्रता के बाद अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की तरह पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक प्रावधानों के तहत परिभाषित करने के अनेक प्रयास किये गये, किन्तु ये प्रयास अन्ततः असफल रहे। क्योंकि कांग्रेस सरकार इस मुद्दे पर सकारात्मक पहल नहीं कर रही थी। 1977 में जनता पार्टी के उदय ने पिछड़ा वर्ग के मुद्दे को प्रमुख राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया। जनता पार्टी द्वारा अपने चुनावी घोषणा पत्र में यह कहा गया कि, जनता पार्टी की सरकार बनने पर एक नया अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया जायेगा। आयोग की संस्तुतियों के आधार पर पिछड़ा वर्ग की पहचान कर उन्हें सरकारी नौकरियों में उचित प्रतिनिधित्व प्रदान करने के उपाय किये जायेंगे।[1] इस दौरान उत्तर प्रदेश एवं बिहार में जनता पार्टी की सरकारें बनी। उत्तर प्रदेष में राम नरेश यादव मुख्यमंत्री बने। इसी समय उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पहली बार पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का प्रावधान किया गया। चूँकि उत्तर प्रदेश में जनता पार्टी को पिछड़ा वर्ग के लोगों का समर्थन प्राप्त था। इसलिए प्रदेश सरकार द्वारा पिछड़ा वर्ग के हितों को ध्यान में रखकर उसके पक्ष में

नीतियों का निर्माण किया गया।[2] उत्तर प्रदेश मे पिछड़ा वर्ग आंदोलन अब आरक्षण की राजनीति से आन्दोलित होना आरंभ हुआ। अब प्रदेश की राजनीति आरक्षण के इर्द–गिर्द घूमने लगी।

1977 में केन्द्र में जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद उत्तर प्रदेश में पिछड़ी जातियों को आरक्षण प्रदान किया गया, जो कि जनता पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में शामिल था। इस दौरान उत्तर प्रदेश में किसान राजनीति कमजोर पड़ने लगी। क्योंकि चरण सिंह इस नीति से बड़े किसान एवं मध्यवर्ती किसान ही अधिक लाभान्वित हुए, जबकि पिछड़ा वर्ग की बहुत सी ऐसी जातियाँ जिनके पास जमीनें नहीं थी? उनकी स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं हो पाया। उत्तर प्रदेश में इन जातियों को जनता पार्टी के घोषणा पत्र ने अधिक प्रभावित किया।[3] 1977 के बाद उत्तर प्रदेश में पिछड़ा वर्ग आन्दोलन मुख्य रूप से आरक्षण को लेकर अधिक मुखरित हुआ। केन्द्र में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी का गठन हुआ, जिसमें चरण सिंह की पार्टी भारतीय लोकसदन की भूमिका महत्वपूर्ण थी। उत्तर प्रदेश में राम नरेश यादव के नेतृत्व में गैर कांग्रेसी सरकार बनी। राम नरेश यादव आचार्य नरेन्द्र देव से प्रभावित थे। अपने छात्र जीवन में ही वे समाजवादी विचारधारा की तरफ आकर्षित हुए।[4] राम नरेश यादव द्वारा उत्तर प्रदेश में किसानों के हितो का ख्याल रखा गया। उनके उत्पादों को उचित मूल्य दिलाने का प्रयास किया गया। ऐसा मुख्य रूप से चरण सिंह के प्रभाव के कारण रहा। दूसरी तरफ आरक्षण पर विशेष ध्यान दिया गया और 1975 में छेंदीलाल साथी के नेतृत्व में गठित सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 25 प्रतिशत आरक्षण पिछड़ा वर्ग को पहली बार दिया गया।

IJRSSH

1967 में लोहिया की मृत्यु के बाद उत्तर प्रदेश में एक नये राजनीतिक परिदृष्य का जन्म हुआ। समाजवादी नेताओं में उत्तराधिकार तथा नई परिस्थितियों में कांग्रेस के साथ संबंध स्थापित करने को लेकर मतभेद उत्पन्न हो गया। मधुलिमये एवं जार्ज फर्नांडीज जैसे समाजवादी नेता कांग्रेस विरोधी नीतियों को त्यागने के पक्ष में थे। वे प्रजा सोशलिस्ट पार्टी एवं संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का विलय करना चाहते थे। किंतु उत्तर प्रदेश में राज नारायण उसके पक्ष में नही थे। उत्तर प्रदेश संसोपा का मजबूत आधार बना।[6] राजनारायण जाति के भूमिहार थे। वे वाराणसी के रहने वाले थे। अपने छात्र जीवन से ही वे समाजवादी विचारधारा से प्रभावित थे। राज नारायण ने सभी समाजवादियों से अपील की आपस में मिलकर आधारभूत मुद्दों को लेकर बातचीत के जरिये हल निकाला जा सकता है। इस तरह नये तरीके से संगठन स्थापित किया जा सकता है।

राज नारायण के कुछ विचार चौधरी चरण सिंह से मिलते थे और वे बी0के0डी0 को कांग्रेस के विरूद्ध एक अच्छी पार्टी के तौर पर देखते थे। उनका मानना था कि बी0के0डी0 के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में एक मजबूत राजनीतिक आधार बनाया जा सकता है। किंतु चरण सिंह पार्टी के अन्दर समाजवादी विचारधारा को अधिक पसंद नहीं करते थे और न ही वे समाजवादियों की तरह लोकतांत्रीकरण के पक्ष में थे। लेकिन चरण सिंह को यह पता था कि समाजवादियों के सहयोग से उत्तर प्रदेश में उनकी पार्टी कांग्रेस के विरूद्ध राजनीतिक बढ़त हासिल कर सकती है। इसलिए राज नारायण के साथ उनका गठजोड़ फायदेमंद हो सकता था। 1974 में बी0के0डी0 एवं संसोपा के आपस में विलय के पश्चात् भारतीय लोकदल (बी0एल0डी0) में अब पिछड़े वर्ग के आरक्षण संबंधी मामले को महत्व प्रदान

IJRSSH

(IJRSSH) 2013, Vol. No. 3, Issue No. II, Apr-Jun ISSN: 2249-4642

किया जाने लगा, जिसे 1971 तक चरण सिंह अपना समर्थन नहीं प्रदान करते थे। किंतु चरण सिंह के विचारों में ऐसा बदलाव मुख्यतः समाजवादी विचारधारा एवं राजनारायण के प्रभाव के कारण हुआ। 1974 में चुनाव के दौरान (बी0एल0डी0) के घोषणा पत्र में पहली बार पिछड़े वर्ग के आरक्षण का समर्थन किया गया। अपने पक्ष में बी0एल0डी0 द्वारा यह दलील दी गयी कि संख्या में सर्वाधिक होने के बावजूद सरकारी नौकरियों में इस वर्ग का प्रतिनिधित्व बहुत ही कम या नाममात्र का है चूँकि इस वर्ग को उचित प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए आरक्षण एक अच्छा तरीका है इसलिए वर्ग को समुचित प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए आरक्षण दिया जाना चाहिए।[7]

1977 में उत्तर प्रदेश एवं बिहार में बनी सरकारों द्वारा पिछड़े वर्गो को दिये गये आरक्षण का समर्थन चरण सिंह ने किया। उनका मानना था कि स्वतंत्रता के बाद अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को आरक्षण प्रदान करने से उनका प्रतिनिधित्व पिछड़ा वर्ग की अपेक्षा अच्छा है। चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पिछड़ा वर्ग को प्रदान किये गये 25 प्रतिशत आरक्षण को न्यायसंगत मानते थे। इसके लिए वे संख्या के आधार पर किसी प्रकार का तर्क करने से बचते थे।

1977–80 का दौर उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्गो की राजनीतिक सक्रियता के संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण था। उस समय राम नरेश यादव के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में जनता सरकार का गठन किया गया और पिछड़ों को 25 प्रतिशत आरक्षण भी प्रदान किया गया। यह पिछड़े वर्गो की राजनीति में बढ़ती भागीदारी का ही परिणाम था। पिछड़े वर्ग के दबाव के कारण ही केन्द्र में मोरारजी देसाई की जनता सरकार ने अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण के मामले पर विचार करने के लिए 20 दिसम्बर 1978 को बिहार के पूर्व

IJRSSH

मुख्यमंत्री बी0पी0 मण्डल की अध्यक्षता में छः सदस्यों वाले आयोग का गठन किया इसे मण्डल आयोग के नाम से जाना गया।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची–

1– ग्लैण्टियर, मार्क, हू आर द अॅदर बैकवर्ड क्लासेस? इन इन्ट्रोडक्शन टू ए कॉस्टीट्यूशनल पॅजल ई0पी0डब्लू0, अक्टूबर 28, 1978 पृ0 1872

2– वही

3– नाइक जे0ए0 द ग्रेट जनता रिवोल्यूशन, नई दिल्ली, चन्द्र एस0 1977, पृ0 157

4– सिंह जी0 (सं0) इंडियाज हूज हू एण्ड इयर बुक, 1977–78, नई दिल्ली, अल्फा पब्लिकेशन, 1978 पृ0 29

5– जेफरेलॉट, क्रिस्टोफे, साइलेण्ट रिवोल्यूशन इन इंडियाः द राइज ऑफ लो कास्ट्स इन नार्थ इंडियन पॉलिटिक्स, परमानेन्ट ब्लैक, दिल्ली 2003 पृ0 306–307

6– वही, पृ0 307

7– वही, पृ0 307–308

IJRSSH

REFERENCES

1. Glantier, Mark, Who are the other Backward classes? In introduction to a Constitutional Puzzle EPW, October 28, 1978, pg 1872
2. Ibid
3. Nike J.A., The Great Janta Revolution, New Delhi, Chandra S. 1977, pg 157

4. Singh G., India's Who's Who and Year Book, 1977-78, New Delhi, Alpha Publication, 1978, pg 29
5. Geoffreylot, Kristofe, Silent Revolution in India: The Rise of Low Castes in North Indian Politics, Permanent Blake, Delhi 2003, pg 306-307
6. Ibid, pg 307
7. Ibid, pg 307-308

IJRSSH